

सत्य का ब्रह्मास्त्र ♦

स्वतंत्र बौद्धिक पत्र

खबरों के लिए लिए लॉगिन करें।

<https://sbpatra.in/>

साप्ताहिक

सम्पादक मधुसूदन शर्मा

वर्ष-३ अंक-१६

नीमच-बुधवार ०८/०७/२०२०

पृष्ठ-४

मूल्य-२

सम्पादकीय

विरोध का

लक्ष्य बड़ा हो - २

चीन के पड़ोसी देश उसकी हड़पनीति से खुश नहीं है। चीन दूसरे देशों की जमीन पर अपना हक जमाता है और फिर शांति की बातें करने का ढोंग करता है। चीनी सेना ने लद्दाख की गलवन घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों को जिस तरह निशाना बनाया, उसके बाद चीन से रिश्ते सामान्य बने रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। चीन ने दशकों पुराने संबंधों में जहर घोलने का काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने ऐसा जान-बूझकर किया है ताकि देश-दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से उपजी महामारी से हटा सके। यह अच्छा हुआ कि चीन की धोखेबाजी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दो-टुक शब्दों में कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हर हाल में होगी। चीन ने अपनी हरकत से खुद को भारत का शत्रु साबित किया है। चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की झलक उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान से मिली, जिसमें उसने गलवन घाटी पर दावा जताते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन तो भारतीय सेना ने किया है। यह चोरी और सीनाजोरी है। जिस गलवन घाटी का कोई चीनी नाम तक नहीं, उस पर वह अपना दावा कर रहा है।

चीन पहले दूसरे देशों की जमीन पर छल-कपट से कब्जा जमाता है और फिर शांति की बातें करने का ढोंग करता है। भारतीय विदेश मंत्री ने उसके ढोंग की पोल खोलते हुए यह सही कहा कि गलवन में जो कुछ हुआ, उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। चूंकि चीन अपनी तानाशाही का प्रदर्शन करते हुए अन्य पड़ोसी देशों को भी तंग करने में लगा हुआ है इसलिए भारत को उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय होने के साथ ही उससे पीड़ित देशों के साथ भी खड़ा होना होगा। चीन को यह बताने की सख्त जरूरत है कि वह अपनी शर्तों पर रिश्ते कायम नहीं कर सकता। चीन के इस मुगालते को भी दूर करना होगा कि उसके बगैर भारत का काम नहीं चल सकता। निःसंदेह चीन से आर्थिक-व्यापारिक दूरी बनाने से कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन उसका सामना करने की सामर्थ्य जुटाना ही आज की सबसे बड़ी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए देश की जनता को भी प्राणपण से जुटना होगा।

— सम्पादक —

५ हेक्टेयर से अधिक चरनोंई भूमि पर दबंगों का अतिक्रमण

ग्रामीणों ने जिलाधीश से मिलकर अतिक्रमण हटाने का दिया ज्ञापन

निर्मल मुदडा - ग्राम पंचायत आलौरी गरवाडा के सरपंच एवं ग्राम वासियों ने क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक देव स्थल जराड महादेव के समीप लगी चरनोंई की भूमि से दबंगों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को हटाकर चरनोंई भूमि को अतिक्रमण कर्ताओं के चंगुल से मुक्त करने हेतु जिला कलेक्टर महोदय नीमच के नाम एक ज्ञापन तत्पा कार्यालय रतनगढ़ पर दिया गया जिसमें मांग की गई कि आलौरी गरवाडा पंचायत क्षेत्र के प्रसिद्ध चमत्कारिक धार्मिक स्थल जराड महादेव के समीप लगभग ५ हेक्टेयर से भी अधिक चरनोंई की भूमि पर ग्राम के ही कुछ दबंगों ने जबरन अवैध कब्जा कर चारों तरफ पत्थरों की ऊंची दीवार बना ली है इसके साथ ही शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन कर चोरी-छिपे पत्थर निकालकर बाउंड्रीवॉल भी बनाई जा रही है।



जिला कलेक्टर महोदय के नाम दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने ग्राम के मनोज पिता देवीलाल धाकड़ निवासी आलौरी एवं आसिफ खान पिता मुब्ना खान पठान एवं उसके भाइयों सहित अन्य कई लोगों के द्वारा अवैध रूप से चरनोंई भूमि पर प्रशासन की मिली भगत से कब्जा करने का आरोप लगाया है ग्रामीणों के द्वारा कई बार इन लोगों से आग्रह करने के पश्चात भी इन्होंने अपना अवैध अतिक्रमण चरनोंई की भूमि से नहीं हटाया है उल्टा प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होने से इन दबंगों के हौसले बुलंद हैं इस संबंध में आलौरी गरवाडा ग्राम पंचायत के सरपंच विनय कुमार चारण, लक्ष्मीनारायण चारण, जोगेंद्र चारण, कालूराम चारण, मुरली चारण, राकेश चारण, जगदीशचन्द्र चारण, सौदानलाल चारण, केशव प्रसाद चारण सहित समस्त ग्रामवासीयों

आलौरी गरवाडा के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय नीमच, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद, तहसीलदार महोदय तत्पा रतनगढ़ के नाम विरदावर अशोक कुमार सेन को ज्ञापन दिया एवं अतिशीघ्र अवैध अतिक्रमण हटवा कर क्षेत्र के ग्रामीणों की गायों को चरने की चरनोंई भूमि को अतिक्रमण कर्ताओं से मुक्त किए जाने की मांग की है। इस संबंध में आज जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच में पहुंचकर जिला कलेक्टर महोदय जितेंद्रसिंह राजे को भी आलौरी गरवाडा के ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अति शीघ्र अतिक्रमण कर्ताओं के चंगुल से चरनोंई भूमि को मुक्त कराने का निवेदन किया गया। इनका कहना है - कल राजस्व निरीक्षक के साथ वहां जाकर स्थिति का अवलोकन करेंगे अगर वहां पर अतिक्रमण पाया गया तो निश्चित रूप से हम वहां का अतिक्रमण हटाएंगे एम.एस.डांगी नायब तहसीलदार रतनगढ़

रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा लॉक डाउन - गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर रविवार को पूरे राज्य में लॉक डाउन रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब हर रविवार को संपूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा लॉकडाउन। राज्य में चलाए रहे किल कोरोना अभियान के तहत ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों से मध्य प्रदेश की परिस्थितियां बदल रही हैं। इस कारण अन्य प्रदेश में आने-जाने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच की जाएगी। आज भोपाल में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के कुछ जिलों, विशेषकर सीमावर्ती जिलों से कोरोना के अधिक मामले आने से प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट बढ़ी है। प्रदेश में पहले

कोरोना ग्रोथ रेट १.७२ थी, जो बढ़कर २.०१ हो गई है। सभी जिलों में मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जाए। सभी सीमावर्ती जिलों में पब्लिक एडवाइजरी जारी की जाए। सभी जिलों में सप्ताह में एक दिन आवश्यक प्रतिबंध लागू किए जाएं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य डॉ. मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे। मुख्य सचिव एवं डीजीपी तैयार करें मैकेनिज्म मध्यप्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। ४२ फीसद आबादी का सर्वे हो चुका है। इसमें एक हजार ७७२ संभावित मलेरिया और २९ डेंगू के मरीज मिले हैं। ५८३ कोरोना

पॉजिटिव सर्वे में सामने आए हैं। मध्यप्रदेश में तो कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन, सीमावर्ती जिलों की स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान के धौलपुर से लगे हुए मुरैना में होने वाली आवाजाही से स्थितियां थोड़ी बदली हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के जलगांव से बड़वानी में लोग आए हैं जिससे स्थितियां बदल रही हैं। बड़वानी, मुरैना एवं अन्य सीमावर्ती जिलों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहां सीमा पार दूसरे प्रांतों में संक्रमण अधिक होने से इन जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं डीजीपी को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में मैकेनिज्म तैयार कर पब्लिक एडवाइजरी जारी करें। हमें प्रदेश में हर स्थान पर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से हर-हाल में रोकना है।

जावद तहसील के १५ कंटेनमेंट एरिया हुए मुक्त,

नीमच। जावद - नई गाइड लाइन के अनुसार कंटेनमेंट एरिया को मुक्त करने में जिले को बड़ी राहत मिली है। इसका सबसे बड़ा लाभ जावद मुख्यालय को मिला। शुक्रवार को जावद क्षेत्र के 13 कंटेनमेंट एरिया एक साथ मुक्त कर दिए गए। यहां आवाजाही शुरू हो गई। जिला मुख्यालय पर दो कंटेनमेंट एरिया हटा दिए गए। कलेक्टर जितेंद्रसिंह राजे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, एडीएम पीएल देवड़ा सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जावद में सिर्फ वार्ड क्र. 12 कंटेनमेंट एरिया के रूप में शेष रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले में जावद ही कोरोना संक्रमण की सबसे अधिक चपेट में आया। यहां लगभग 350 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि स्वस्थ होने वाले अधिकांश लोग भी इसी नगर के हैं जो अब अपने घरों में हैं। शुक्रवार शाम तक कुल संक्रमितों की संख्या 453 है, जबकि स्वस्थ होने वाले 428 लोग हैं जो सकुशल लौट गए। जिले में मात्र 17 एक्टिव केस शेष बचे हैं। जिले के नौ लोगों की मौत भी हो चुकी है। शारीरिक दूरी और मास्क का करें उपयोग ओर बचे वयरस से

कंटेनमेंट एरिया मुक्त होने के बाद निरीक्षण के दौरान कलेक्टर राजे ने कहा कि क्षेत्रवासियों को अब अधिक सावधानी से रहना होगा। आवाजाही के दौरान शारीरिक दूरी का पालन व मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने क्षेत्रवासियों को स्वस्थ होने और नियमों का पालन करने पर शुभकामनाएं व बधाई दी। शुक्रवार को उम्मेदपुरा, तारापुर, इंगरपुरिया, बावल नई, माणक चौक, सिलावटी मोहल्ला, मोतीपुरा, धान मंडी, आचार्य हुकमीचंद मार्ग, ओझा घाटी, रामपुरा दरवाजा, बिचली गली, बोहरा गली क्षेत्र मुक्त हुए। जिला मुख्यालय पर राजस्व कलोनी व बड़ी मंडी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए। स्वास्थ्य विभाग ने की एक लाख 35 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग जिलेभर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक लाख 35 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सीएमचओ डॉ. महेश मालवीय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिले में सक्रियता के साथ स्क्रीनिंग का कार्य कर रहे हैं। जिले में पहली जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। इस अभियान में शामिल सर्वेद दल ने भी तीन दिन की अवधि में जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों के सैंपल लिए हैं। जिले में कुल 8 स्वास्थ्य संस्थाओं पर फीवर क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है।

नही लगेगा सुखानंद का मेला कोरोना वायरस को देख उठाया कदम।

प्रकृति की गोद में बसे सुखानंद महादेव धाम में इस वर्ष मेला आयोजित नहीं होगा। कोविड-१९ के संक्रमण और बचाव के मद्देनजर यह बड़ा निर्णय लिया गया है। जावद मुख्यालय पर हुई प्रशासनिक और मंदिर समिति की बैठक में यह तय किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि इस बार सावन माह में आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। उल्लेखनीय है कि इस मेले का आयोजन इस वर्ष ६ जुलाई से ५ अगस्त तक प्रस्तावित था। बड़े आयोजनों की तर्ज पर इस मेले के आयोजन पर भी रोक लगा दी है। इसमें मंदिर समिति के पदेन अध्यक्ष एसडीएम पीएल देवड़ा, एसडीओपी एमएल मोरे, तहसीलदार विवेक कुमार गुप्ता, टीआई ओपी मिश्रा, प्रशासनिक अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंदिर समिति की ओर से प्रबंधन बंशीलाल नागदा, गोपाल चारण, मदनलाल धाकड़, रामलाल भाया कीर, शांतिलाल चौहान, सचिन गोखरू, सरपंच प्रतिनिधि सचिव ओमप्रकाश पाराशर, पवन पाराशर आदि मौजूद थे। इस मेले में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

लगेगे बेरिकेड्स, प्रवेश वर्जित इस बैठक में समिति में निर्णय लिया कि पूरे सावन माह मेला अवधि में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित होगा। यहां बेरिकेड्स लगाए जाएंगे। जगह-जगह पोस्टर-बैनर के माध्यम से मेला आयोजन स्थगित होने और प्रवेश निषेध की सूचना लगाई जाएगी। गौरतलब है कि इस मेले के आयोजन में महादेव मंदिर में आकर श्रद्धालु पूजा-अर्चना व विशेष अभिषेक करते हैं। इस वर्ष यह संभव नहीं हो सकेगा। जगह-जगह बेरिकेड्स लगाए जाएंगे। पदेन अध्यक्ष देवड़ा ने कहा कि सिर्फ मंदिर में पुजारी नियमित पूजा-अर्चना करेंगे। समिति सदस्यों को छोड़कर अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक है। विशेष परिस्थिति में पदेन अध्यक्ष से अनुमति लेकर प्रवेश दिया जा सकेगा। मंत्र व राजस्थान सीमा पर स्थित मंदिर के ऊपरी हिस्से में पहाड़ी पर भी बेरिकेड्स लगाए जाने का निर्णय लिया। राजस्थान के कनेरा आरक्षी केंद्र के थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

जावद विधानसभा में जाट में गौशाला बनकर हुई तैयार, गौमाता को रहने के लिए लोकार्पण का इंतजार

नीमच। मध्यप्रदेश सरकार ने गौमाता को आसरा देने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्व सुविधा युक्त गौशाला का निर्माण करने की घोषणा की गई थी इसी के तहत नीमच जिले में भी शासन के द्वारा ६ गौशाला स्वीकृत की गई थी जिसके अंतर्गत जावद तहसील के ग्राम पंचायतों में जाट पंचायत में क्षेत्र की सबसे पहली सर्व सुविधा युक्त गौशाला बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई है उक्त सर्व सुविधा युक्त गौशाला का निर्माण जाट रतनगढ़ मार्ग पर सड़क किनारे २.५० हेक्टेयर भूमि यानी १२ बिघा जमीन पर २६ लाख रुपये की लागत से पूर्ण किया गया। गौशाला का पूरा निर्माण रंग रोगन एवं आकर्षक

चित्रकारी से परिपूर्ण हो चुका है अब बस ग्राम वासीयो एवं गौमाताओं को गौशाला के लोकार्पण का बेसब्री से इंतजार है। गौशाला के अंदर लगभग १०० गायों को आसानी से सर्व सुविधायुक्त वातावरण में रखा जा सकेगा। गौशाला में सभी गायों के चारे पानी के साथ ही स्वच्छ हवा, प्रकाश की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है पीने के पानी के लिए के लिए एक ट्यूबवेल का खनन कर उसमें मोटर भी लगा दी गई है इसके साथ ही गायों को पीने के लिए एक पानी का बड़ा होद (खैर) भी बनाई गई है।

इसके साथ ही गौशाला के बीच में एक खुला मैदान भी बनाया गया है जिससे गायों को खुले मैदान में स्वच्छंदता से विचरण करने में आसानी रह सकेगी। गौशाला में गायों के छोटे छोटे बछड़े बछड़ीयों के लिये चार बछड़ा रूम भी बनाए गए हैं इसके साथ ही गौशाला में रखी गई सभी गायों की सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकीदार रूम भी बनाया गया है। गौशाला के लोकार्पण के साथ ही अतिशीघ्र गौशाला की संपूर्ण व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासन के सहयोग से ग्रामीणों की एक समिति बनाई जाएगी।

जावरा दुल्हन की हत्या का मुख्य आरोपित राजस्थान से गिरफ्तार

रतलाम- जावरा। शादी के कुछ समय पहले जावरा के ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा रही दुल्हन सोनू यादव की रविवार सुबह गला रेतकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपित भाजयुमो के पूर्व मंडल मंत्री राम यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को पत्रकार वार्ता में एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि हत्या के बाद राम यादव व पवन पांचाल बाइक से पिपलौदा, सैलाना होते हुए बांसवाड़ा भाग गए। बांसवाड़ा में राम को छोड़कर पवन वापस रतलाम आने लगा तो रास्ते में पकड़ा गया। राम यादव को राजस्थान के निम्बाहेड़ा जिले में स्थित सांवरियाजी परिसर से रविवार रात गिरफ्तार किया गया। दोनों को सोमवार को जावरा न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नमिता बौरासी के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने नौ जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए। हत्या के बाद जावरा सीएसपी प्रदीपसिंह राणावत व शहर थाना प्रभारी वीडी जोशी घटनास्थल पहुंचे थे। जांच में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में युवक ब्यूटी पार्लर में घुसने और कुछ देर बाद बाहर निकलकर भागते हुए दिखा। साथ ही पार्लर के बाहर बाइक (एमपी 43-डीटी 8979) पर दो व्यक्ति जाते दिखे।

रतलाम के सीसीटीवी कैमरे में भी इस बाइक से सुबह साढ़े छह बजे दो व्यक्ति निकलते दिखे। दीनदयाल नगर थाने के आरक्षक अभिषेक पाठक ने उनकी पहचान 25 वर्षीय राम यादव व उसका साथी 23 वर्षीय पवन पांचाल निवासी जाटों का वास रतलाम के रूप में की। पुलिस ने सोनू यादव के मोबाइल पर आखिरी कॉल के नम्बर की जांच की तो वह पवन का निकला। हालांकि हत्या के कुछ घंटे बाद ही आरोपित पवन को बाइक पर राजस्थान की तरफ से आते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने राम यादव को बांसवाड़ा डिपो तक छोड़कर आने की जानकारी दी। इसके बाद टीम बांसवाड़ा भेजी गई। इसी बीच पवन ने राम यादव को सांवरियाजी की तरफ रवाना करना बताया। तब टीम सांवरियाजी भेजी गई और वहां से राम यादव को पकड़ लिया गया।

यह था मामला - सोनू पुत्री कमलसिंह यादव निवासी नागिन कॉलोनी शाजापुर की जावरा के ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के दौरान गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। सोनू का विवाह नागदा के गौरव जैन से होना था। आठ साल पहले शादी टूटने के बाद सोनू के दूसरे विवाह की तैयारी की गई थी। वह शाजापुर में सरस्वती विद्यालय में उप प्राचार्य थी। तीन साल पहले आरोपित राम यादव से संपर्क होने के बाद दोनों मैसजर व मोबाइल पर बात करते थे। सोनू यादव ने चार-पांच दिन पहले राम को फोन कर सगाई व शादी के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि अब फोन मत लगाना। राम ने उसे शादी करने से मना किया लेकिन सोनू ने परिजन के फैसेले के अनुसार शादी करने की बात कही। इस पर आरोपित ने दोस्त पवन पांचाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। (नईदुनिया वेबसाइट)

करंट से युवक की मौत

नीमच। करंट लगने से एक युवक की मौत हुई है। नीमच सिटी पुलिस ने बताया कि भादवामाता में शिवलाल पुत्र देवीलाल बलाई की करंट लगने से मौत हो गई। युवक छत पर त्रिपाल सुखाने के लिए छत पर गया था, इस दौरान युवक को करंट लग गया। पुलिस ने शव का पीएम कराकर शव स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। वही मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

कुएं में डूबने से युवती की मौत

नीमच। एक युवती की कुएं में डूबने से मौत हुई है। बघाना पुलिस ने बताया कि हवाई पट्टी रोड स्थित नीमच। एक युवती की कुएं में डूबने से मौत हुई है। बघाना पुलिस ने बताया कि हवाई पट्टी रोड स्थित पितृ वाटिका के पास सुबह निर्माणधीन कुएं में डूबने से १७ वर्षीय निकिता पुत्री सज्जनलाल चौहान की मौत हो गई। निकिता व उसकी सहेली पूजा बावरी सुबह बकरियां चराने गई थीं। इस दौरान दोनों निर्माणधीन कुएं में गिर गईं। जहां से पूजा को बचा लिया गया, लेकिन निकिता की डूबने से मौत हो गई। उसकी बुआ पूजा पत्नी राजू भील ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के जिला अस्पताल भेजा। जहां शव का पैनल से पीएम कराकर शव स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम का जांच में लिया है।

स्कूल फीस को लेकर सभी याचिकाओं पर अब जबलपुर हाईकोर्ट में होंगी सुनवाई

निजी स्कूलों की फीस को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में लगी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जबलपुर। निजी स्कूलों की फीस को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में लगी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ के समक्ष राज्य की निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने १३ जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी। इस बीच इंदौर और ग्वालियर बेंच के भी स्कूल फीस संबंधी केस जबलपुर ट्रांसफर होंगे। जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर

के डह. पीजी नाजपाण्डे और रजत भार्गव का पक्ष अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग से रखा। उन्होंने जबलपुर में जस्टिस अतुल श्रीधरन और इंदौर में जस्टिस सतीश शर्मा के विरोधाभासी आदेशों को रेखांकित किया। दो अलग-अलग आदेश पारित हुए उन्होंने साफ किया कि निजी स्कूलों की फीस वसूली के बिन्दु पर हाई कोर्ट की दो बेंचों ने अलग-अलग आदेश पारित कर दिए हैं। इंदौर बेंच ने निजी स्कूलों को शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अलावा अन्य शुल्क भी वसूलने स्वतंत्र करते हुए राज्य शासन के सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी। जबकि हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर ने इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों द्वारा

शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य शुल्क वसूल जाने पर अंतरिम रोक लगा दी। इस तरह एक ही मुद्दे पर हाई कोर्ट के दो विरोधाभासी अंतरिम आदेश सामने आए। ऐसे में महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु का निर्धारण आवश्यक प्रतीत हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश देगे आगे की व्यवस्था इंदौर बेंच ने साफ कर दिया कि अब स्कूल फीस संबंधी सभी याचिकाएं संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में ही सुनी जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश ही इस संबंध में बेंच के निर्धारण की व्यवस्था को अंतिम रूप देगे। संभावना यही है कि उनकी अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष यह मामला विचारण के लिए निर्धारित होगा। जबलपुर से इंदौर बेंच के स्टे को दी गई थी चुनौती न्यायिक उपभोक्ता मार्गदर्शक

मंच के प्रांताध्यक्ष जबलपुर निवासी डह.पीजी नाजपाण्डे व रजत भार्गव ने एक अंतरिम आवेदन के जरिए इंदौर बेंच द्वारा राज्य शासन के सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने संबंधी अंतरिम स्थानादेश को चुनौती दी गई थी। मांग की गई थी कि स्टे अहडर वापस लिया जाए। इंदौर बेंच ने विरोधाभासी दो आदेशों के कारण कोई आदेश पारित न करते हुए समग्र केस मुख्यपीठ ट्रांसफर करने की व्यवस्था दे दी। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अवगत कराया कि अब जबलपुर में स्कूल फीस को लेकर दायर फ्रेश पीआईएल के अलावा इंदौर व ग्वालियर बेंच में दायर नई व पुरानी पीआईएल भी जबलपुर में यूनिफाइड रूप से लिंक-क्लब करके सुनी जाएंगी।

कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों के विभागों पर होगा फैसला – सीएम चौहान

भोपाल। मध्य प्रदेश में ३३ मंत्रियों को विभागों के बंटवारे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सभी विभागों का मंत्री हूं, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। कल कैबिनेट की बैठक है उसके पहले सबकुछ हो जाएगा। मंगलवार को दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों को विभाग बांटने की बात कही थी। एक जुलाई को प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने २० को कैबिनेट और ८ को राज्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसके पहले २१ अप्रैल को ५ कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, इन्हें विभागों का वितरण भी किया गया था। ज्योतिरातिदित्य सिंधिया खेमे के नेताओं को मंत्रिमंडल में तरजीह देने पर भाजपा में कुछ नेता नाराज हैं।

इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय विश्वादे का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। मुझे डर है कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज न हो जाय। नुकसान हो जाएगा। पहले इन पांच मंत्रियों ने २१ अप्रैल को ली थी शपथ नरोत्तम मिश्रा रू गृह विभाग, लोक स्वस्थ एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य संबंधी कार्य कमल पटेल रू कृषि विभाग गोविन्द सिंह राजपूत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता तुलसीराम सिलावट रू जल संसाधन विभाग, मीना सिंह मांडवे आदिम जाति कल्याण इन २८ मंत्रियों ने १ जुलाई को ली शपथ

कैबिनेट मंत्री- गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहू लाल सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, एदल सिंह कंषाना, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसौदिया (संजु भैया), प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओमप्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, डह. मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राजवध नि सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव राज्यमंत्री - भरत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, रामलेखावन पटेल, राम किशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिराज डंडौतिया, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया

कैलाशपति महादेव को भोले भंडारी भोलेनाथ कहा जाता है। क्योंकि वो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मात्र छोटे से उपाय से वो उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की उपासना से भक्तों के कष्टों का नाश होता है और सुख-संपत्ति के साथ आरोग्य और अंत में मोक्ष का वरदान मिलता है। महादेव के अनेक सिद्ध मंत्र हैं, जिनके जाप से भक्तों की मनचाही मुराद पूरी होती है। महादेव का एक ऐसा ही अमोघ रक्षाकवच है महामृत्युंजय मंत्र, जिसके जप से सुख-समृद्धि के साथ बेहतर स्वास्थ्य का वरदान शिव भक्त को मिलता है। अन्नत ऊर्जा और अपार शक्ति से भरपूर इस मंत्र को माना जाता है। सृष्टि में महादेव को सर्वशक्तिमान और ब्रह्माण्ड का स्वामी माना जाता है। इसलिए भगवान शिव के इस मंत्र को महामंत्र का संज्ञा दी गई है। इस मंत्र का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र - श्वाँँँ उत्तम स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप किया जाता है। इससे महादेव के वरदान से शरीर स्वस्थ और सेहत दुरुस्थ रहती है। त्र्यक्षरी महामृत्युंजय मंत्र - रुँँँ जूंँँ सरुँँ कोई सामान्य रोग यदि लंबे समय से परेशान कर रहा हो तो इस मंत्र

का जाप रात्रि में सोने पहले कम से कम २७ बार करें। इससे शिवकृपा मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र - श्वाँँँ हौँँ जूंँ सरुँँ जब आपकी कुंडली में किसी खतरनाक दुर्घटना के या किसी गंभीर बीमारी की अवस्था में सर्जरी के योग हों, तब ऐसी अवस्था में इस तरह के योग को टालने के लिए सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद इस मंत्र की तीन माला का जाप करें। दशाक्षरी महामृत्युंजय महामंत्र - श्वाँँँ जूंँ सरुँँ माम पालय पालय कुंडली में अल्पायु योग या स्वास्थ्य की गंभीर समस्या होने पर इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने के साथ वह लंबी उम्र को प्राप्त करता है। इस मंत्र का अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र - ओम हौँँ जूंँ सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भूः धः सः जूंँ हौँँ ओम ! महामृत्युंजय मंत्र का जाप विधिपूर्वक करने से गंभीर रोग से फायदा होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इसके जाप से कष्टों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।

सिंधिया समर्थक और वरिष्ठ मंत्रियों की खींचतान में अटका विभागों का बंटवारा

रविवार और सोमवार को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरातिदित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विभाग बंटवारे के मुद्दे पर मंथन किया। बताया जा रहा है कि ज्योतिरातिदित्य सिंधिया के कोटे के मंत्रियों के लिए बड़े माने जाने वाले विभाग मांगे जा रहे हैं। दरअसल, २४ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को बड़े विभाग दिलाना चाहते हैं ताकि क्षेत्र में सकारात्मक संदेश जाए। इससे केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री भी सहमत हैं पर वरिष्ठ मंत्रियों की अनदेखी भी न हो, इसके लिए संतुलन बनाने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, उद्योग और जल संसाधन विभाग को लेकर फंस रहा था। मुख्यमंत्री इनमें से कुछ विभाग नए मंत्रियों को देने पर तो सहमत हैं,

लेकिन कुछ विभाग वरिष्ठ मंत्रियों (गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया) को देना चाहते हैं, ताकि संतुलन बना रहे। वैसे भी सियासी समीकरणों के चलते कुछ वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया, जिसे लेकर असंतोष भी सतह पर आ चुका है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने दो दिन दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी पहलुओं पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक, दो दिन के मंथन के बाद विभागों के बंटवारे की रणनीति तय हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ मुख्यमंत्री के बैठक के बाद संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को विभागों का बंटवारा हो जाएगा। पांच मंत्रियों (डॉ. नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और मीना सिंह) म से कुछ के विभागों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ राज्यमंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। चुनावी समीकरणों पर भी ध्यान - सूत्रों का कहना है कि जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार में २४ विधानसभा के उपचुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखा गया, ठीक वैसा ही विभागों के बंटवारे को लेकर भी हो रहा है।

बताया जा रहा है कि आमजन से सीधा सरोकार रखने वाले विभागों को मुख्यमंत्री ऐसे मंत्रियों के पास रखना चाहते हैं, जिनके पास उपचुनाव जैसी परिस्थिति में काम करने और कराने का पूर्व अनुभव हो। चाहे गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास हो या फिर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इनका सीधा वास्ता तो ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का पूर्व अनुभव नहीं है। चुनावी जमावट से रहता है। १६ विधायक पहली बार बने हैं मंत्री - मंत्रिमंडल में १६ नेताइनमें आठ (एदल सिंह कंषाना, प्रेम सिंह पटेल, ओमप्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, डॉ. मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राजवर्द्धन सिंह) कैबिनेट और आठ (भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, रामलेखावन पटेल, रामकिशोर कावरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिराज डंडौतिया, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया) राज्यमंत्री बनाए गए हैं। विभागों में कामकाज हो रहा है प्रभावित - सूत्रों का कहना है कि विभागों का बंटवारे में लग रहे समय का असर कामकाज पर भी पड़ रहा है।

शिव जलामिषेक से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा और होता है पापों का नाश

भगवान भोलेनाथ को प्रकृति से बेहद लगाव है। इसलिए उनका निवास भी प्रकृति की सुरम्य छटा बिखरने वाले कैलाश पर्वत पर है। धरती को पापमुक्त करने वाली मोक्षदायिनी गंगा उनकी जटाओं में विराजमान है। सर्प उनका श्रंगार है। मृगछाल के उनके वस्त्र हैं। बिल्वपत्र उनको प्रिय है, भांग, धतूरे का भोलेनाथ भोग लगाते हैं और इन सबसे बढ़कर जलामिषेक से वो प्रसन्न और त्रुप्त होते हैं। जलामिषेक से होता है कष्टों का नाश - मान्यता है कि शिवलिंग पर जल की धारा समर्पित करने से भक्तों का कल्याण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पंचतत्व में जल को प्रधान तत्व मानते हुए शिवामिषेक का बहुत महत्व बतलाया गया है। शास्त्रों में जल में विष्णु का वास माना गया है, जबकि शिव पुराण में शिव को साक्षात् जल माना गया है। जल को नार भी कहा गया है। इसलिए भगवान लक्ष्मीनारायण ने कहा है कि जल से पृथ्वी की

गरमी दूर होती है इसलिए जो शिवभक्त शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करता है उसके सभा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश हो जाता है। जलामिषेक से होता है नकारात्मक ऊर्जा का नाश - यह भी मान्यता है कि शिव जलामिषेक से मानव के अंदर संग्रहित नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। आध्यात्मिक कारण यह भी है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के मस्तक के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इडा नाडियों का मिलन स्थल है। इससे मानव की सोचने-समझने की शक्ति का संचालन होता है। इसको शिव स्थान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क शांत रहे और उसमें शीतलता बनी रहे इसलिए शिव को जल समर्पित किया जाता है। इस संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी ज्योतिर्लिंगों में रेडिएशन पाया जाता है, जो परमाणु संयंत्र की तरह रेडियो एक्टिव ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए ऊर्जा को शांत रखने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। जलामिषेक का यही जल नदियों में मिलकर औषधिय रूप ले लेता है।

सतर्कता से इन्कार

देश में कोवोना मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। हैरानी है इसके बावजूद लोग अपेक्षित आवश्यकता का पविचय देने से इन्कार कर रहे। कोवोना वायरस के संक्रमण को धामने की तमाम चेष्टा के बाद भी उसके मरीजों की बढ़ती संख्या चिंतित करने वाली है। कुछ समय पहले तक कोवोना संक्रमण से ग्रस्त होने वालों की जो संख्या १० हजार प्रतिदिन थी, वह १५ के बाद ३० हजार हुई और अब ३५ हजार का आंकड़ा पार करती दिखा रही है। यदि इस वृद्धि को धामा नहीं गया तो भारत कोवोना मरीजों की दृष्टि से अमेरिका और ब्राजील के बाद बड़ा नजर आएगा। हालांकि इन दोनों देशों के मुकाबले भारत की आबादी कहीं अधिक है और कोवोना मरीजों की संख्या को कुल आबादी के आपेक्षा ही देखा जाना चाहिए। इसके बावजूद कोवोना मरीजों की बढ़ती संख्या कोई शुभ संकेत नहीं। निःसंदेह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को कोवोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए और अधिक सक्रियता दिखाने और व्यापक टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन बात तो तभी बनेगी जब आम लोग आवश्यक सतर्कता का पविचय देंगे। यह खेद की बात है कि वास्तव में हमने दिखाने के बावजूद लोग अपेक्षित आवश्यकता का पविचय देने से इन्कार कर रहे हैं। आर्थिक वृद्धि पर न जाने कितने ऐसे लोग दिखा जा रहे हैं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। इनसे भी व्यापक बात यह है कि तमाम लोग या तो मास्क लगाते ही नहीं या फिर केवल दिखाने के लिए गले या ठुड़ी पर लटकाए रहते हैं। ऐसा करने से वायरस के साथ औरों को वास्तव में डालने का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि शासन-प्रशासन को इसके लिए बाध्य भी कर रहे कि वे उस लॉकडाउन को लेकर संवर्धन करें, जिससे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। यदि देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की संवर्धन बढ़ानी पड़ रही है तो लोगों की लापरवाही के कारण ही। हैरानी इस पर है कि लोग यह देखा रहे हैं कि अब एक अप्टाह से भी कम समय में एक लाख कोवोना मरीज बढ़ जा रहे हैं, फिर भी जरूरी आवश्यकता नहीं दिख रही है। चौबीस-छपे किस्म-किस्म के आयोजन करना और उनमें भीड़ एकत्रित करना एक किस्म की आपराधिक लापरवाही ही है। इस तरह की लापरवाही पूरे देश के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है, क्योंकि इसके चलते कोवोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और उसके नतीजे में कारोबारी एवं अन्य जरूरी गतिविधियों को गति देने में बाधा आ रही है। निःसंदेह यह वास्तविकता है कि कोवोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ रही है और कई राज्यों में यह दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, लेकिन यदि संक्रमण की वृद्धि पर लगाम नहीं लगी तो हालात अमान्य होने में और अधिक समय लगेगा।

भरोसे लायक नहीं चीन

- लेख

यह ठीक है कि लद्दाख में चीन पीछे हट गया, लेकिन उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आखिरकार चीन लद्दाख में अपने कदम पीछे सींचने के लिए विवश हुआ। उसने डोकलाम के बाद लद्दाख में भी मात खानी पड़ी तो भारत के इसी दृढ़ इरादे के कारण कि उसकी दावागिरी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री का लेंह दौरा देश के इसी दृढ़ इरादे को रेखांकित करने वाला था। यह उल्लेखनीय है कि डोकलाम के मुकाबले लद्दाख में चीन को कहीं जल्द समझ आ गया कि भारत से उलझना महंगा पड़ेगा। चीनी सेना लद्दाख से जिस तरह पीछे हटने को बाध्य हुई उससे दुनिया को यही संदेश गया कि चीन से आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत है। चीन के खिलाफ यह जो संदेश गया, उससे विश्व समुदाय में भारत की अहमियत तो बढ़ेगी ही, चीन की हस्तियों से परेशान देशों का मनोबल भी बढ़ेगा।

चूंकि भारत सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में चीन को दबाव में लाने पर कामयाब रहा, इसलिए अब उसी इसके लिए कोशिश तेज कर देनी चाहिए कि यदि चीनी सत्ता समुच्च भारत से संबंध सुधारना चाहती है तो सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे आए। अभी तक चीन सीमा विवाद सुलझाने का नाटक ही करता आ रहा है। भारत को इस नाटकबाजी पर पर्दा डालने के लिए सक्रिय होना होगा। इसी के साथ भारतीय सेना को चीन से लगती सीमा पर और अधिक सतर्कता भी बरतनी होगी। उसकी ओर से मित्रता, सहयोग और शांति की बातें करने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। चूंकि चीन भरोसे के काबिल नहीं रहा इसलिए उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने का अभियान प्राथमिकता में बने रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को धत्ता बताने और अपनी स्वतन्त्रता विस्तारवादी प्रवृत्ति बरकरार रखने वाले चीन सरीखे

देश पर आर्थिक निर्भरता जितनी जल्द सत्ता हो उतना ही अच्छा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना केवल इसीलिए आवश्यक नहीं है कि अहंकारी चीन की चुनौतियों का जवाब देना है, बल्कि इसलिए भी है, क्योंकि उससे ही हम अपनी तमाम आंतरिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। वास्तव में आर्थिक रूप से सबल भारत ही विश्व समुदाय में अपनी सही पहचान स्थापित करने में समर्थ होगा। चीन ने लद्दाख में जो संकट खड़ा किया उसका सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी मामले में हम उसके मोहताज न रहें और उसकी संवेदनशीलता की चिंता तभी करें जब वह हमारे हितों की परवाह करें। सरकार और साथ ही कारोबार जगत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले कोरोना के कहर और फिर लद्दाख में तकरार के चलते चीन पर आर्थिक निर्भरता खत्म करने को लेकर जो कदम उठाने शुरू किए गए थे, वे शिथिल न पड़ें पाए।

जरूरी है चीन को उचित जवाब देना

भारत गलबन घाटी में चीन की धोखेबाजी का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसे प्रधानमंत्री ने लेह दौरे के अपने उस संबोधन से और अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने चीन को विस्तारवादी बताया। चीनी दुस्साहस के प्रतिकार का सबसे सही तरीका यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसकी मजबूत पकड़ को ढीला किया जाए। इससे ही उसे सबक मिलेगा, क्योंकि वह अपनी आर्थिक ताकत के जरिये अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।

बहरहाल, यह बहस का विषय हो सकता है कि आखिर भारत चीन के आर्थिक चुंगुल में क्यों फंसा, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि जब चीनी कंपनियां सस्ता माल उपलब्ध कराएंगी तो कोई भी देश उन्हें खरीदने के लिए लालायित होगा। आज चीन के सस्ते कच्चे माल और उत्पादों के मामले में जो स्थिति भारत की है, वही दुनिया के अन्य देशों की भी। चीन सस्ते उत्पाद उपलब्ध करने में दरअसल इसलिए सफल हुआ, क्योंकि बीते चार दशकों में इसके लिए उसने न केवल एक अभियान छेड़ा, बल्कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर अपने निर्यात को आकर्षक भी बनाया। इसके चलते ही वह दुनिया का कारखाना बन गया।

भारत १९६२ के युद्ध के बाद कई दशकों तक तो चीन से सशक्त रहा, लेकिन बाद में जब चीनी सत्ता ने अपना रुख बदला तो भारत भी उससे दोस्ताना संबंध कायम करने पर सहमत हो गया। इन दोस्ताना संबंधों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बात होती रही, लेकिन भारत ने इस पर गौर नहीं किया कि चीन इस विवाद को सुलझाने का इच्छुक नहीं। हम यह भी नहीं देख सके कि चीन किस तरह पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हम उसकी संवेदनशीलता की तब भी चिंता करते रहे, जब वह अरुणाचल और कश्मीर को लेकर अपनी बदनीयती दिखाता रहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आर्थिक गलियारे का निर्माण भी उसकी बदनीयती का प्रमाण है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का

भारत में शरण लेना चीन को नागवार गुजरा और वह अभी भी उनके प्रति आक्रामक है। अब जब चीन ने अपने विस्तारवादी इरादे खुलकर जाहिर कर दिए हैं, तब फिर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि भारत अपनी रणनीति बदले। इस बदली हुई रणनीति के तहत चीन के ५९ एप पर पाबंदी लगाने के साथ उसकी कंपनियों को तमाम क्षेत्रों से बाहर किया जा रहा है। इसका चीन पर असर दिखने लगा है। उसने अपने एप पर पाबंदी के खिलाफ डब्ल्यूटीओ जाने की धमकी दी है। हालांकि इससे उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि वह खुद डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करता है। एक आकलन के अनुसार ५९ चीनी एप पर पाबंदी से चीनी कंपनियों को अरबों रुपये की चोट पहुंच सकती है। तकनीक के क्षेत्र में भारत में पैठ बनाने के उनके इरादों पर भी पानी फिरेगा। आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सही कहा कि चीनी एप पर पाबंदी एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक है। भारत के लिए यह भी आवश्यक है कि वह चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर जो आवाज बुलंद हो रही है, उसमें अपना सुर मिलाए। वैसे भी विश्व समुदाय चीन से पहले से ही खफा है, क्योंकि उसकी लापरवाही से ही कोविड-१९ महामारी दुनिया भर में फैली। गलबन घाटी की घटना के बाद कई देशों ने भारत से सहानुभूति भी जताई है। इनमें विकसित देश भी हैं। यह अच्छा हुआ कि अन्य देशों के साथ भारत ने भी यह मांग की है कि इसकी तह तक जाया जाए कि कोरोना वायरस वृहान से निकलकर सारी दुनिया में कैसे फैला चीन को जवाब देने के लिए सैन्य मोर्चे पर भी तैयारी समय की मांग है। भारत ने अपनी सेनाओं के लिए राफेल समेत अन्य लड़ाकू विमान और हथियार एवं उपकरण जुटाने की तैयारी तेज कर दी है। चीन को यह अहसास होना चाहिए कि यह १९६२ वाला भारत नहीं है। चीन को यह संदेश देना जरूरी है कि अगर उसने भारत की जमीन हथियाने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने कीमत चुकानी शुरू भी कर दी है।

अहंकारी चीनी सत्ता के सिर उठा लेने के बाद यह आवश्यक है कि देश के राजनीतिक दल उसके खिलाफ एकजुट हों। यह दुखद ही नहीं, शर्मनाक भी है कि कांग्रेस और वामदल इस एकजुटता में बाधक बन रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री को लांछित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वह छल-कपट का सहारा भी लेने में लगे हुए हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री लेह में थे, उसी दिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें कथित तौर पर लद्दाख के कुछ निवासियों के हवाले से यह बताया गया कि गलबन के हालात को लेकर सरकार जो कह रही है, वह सही नहीं। बाद में पता चला कि लद्दाख के ये कथित नागरिक कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता हैं। यह नकारात्मकता की हद है। राहुल अपनी नकारात्मक बातों से देश की छवि खराब करने के साथ ही राष्ट्रीय हितों पर चोट करते दिख रहे हैं। उनकी बेजा बयानबाजी पर भाजपा ने जो पलटवार किया, उससे यह पता चला कि संग्राम शासन के वक्त कांग्रेस ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से एक वैचारिक समझौता किया। यह समझौता सोनिया और राहुल की वामपंथी सोच को ही उजागर करता है। कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि आखिर इस समझौते से देश को क्या लाभ हुआ? अब तो इसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि २००४ में चीन के साथ जो व्यापार घाटा १.१ अरब डॉलर का था, वह २०१३-१४ में बढ़कर ३६.२ अरब डॉलर का हो गया। भाजपा का आरोप तो यह भी है कि कांग्रेसी नेताओं के वर्चस्व वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से जो चंदा मिला, उसके एवज में चीन के आर्थिक हितों का पोषण किया गया।

मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में चीन के साथ होने वाले व्यापार घाटे को तेजी से पाटने की कोशिश कर रही थी। यह कोशिश तभी कामयाब होगी, जब हमारे कारोबारी भी यह ठान लें कि उन्हें चीन से सस्ता माल नहीं मंगाना। चीन से व्यापार घाटा अकेले सरकार की देन नहीं। तमाम कारोबारियों ने मैयूफैक्टरिंग बंद कर चीन से माल मंगाना शुरू कर इस घाटे को बढ़ाया। अब उन्हें इसे कम करने का काम करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा मकसद चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना ही है। चीन पर आर्थिक निर्भरता को न्यूनतम स्तर पर लाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि समस्त देशवासी हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने वाले दुस्साहसी चीन के प्रतिकार में सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें।